MR. DEPUTY-SPEAKER : No, Mr. Halder. I have gone to the next itsm.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY-SPEAKER : Don't record whatever Mr. Halder says,

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I may request the Minister to use his electronic methods to shorten his statement.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Large-Scale Infiltration Of Pakistani Nationals Into Kutch In North Gujarat And In Other Parts Of The Country.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर गृह मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में वक्तव्य दें : "उत्तर गुजरात के सीमावर्ती कच्छ जिले में तथा देश के विभिन्न भागों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की बड़े पैमाने पर कथित घुसपैठ से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

THE MINISTER OF HOME AFFIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, Gujarat-Pakistan broder covers a length of 512 Kms in which there are 21 border out-posts of the Border Security Force for checking illegal entry into India. There is a proposal to further strengthen vigilance by establishing a few more border out-posts of the B.S.F. During 1983 (upto June), the B.S.F. apprehended 14 Pak nationals on Kutch-Pakistan border who were found crossing the border illegally. Action is being taken against them by local authorities under the law; In addition, local civil and armed police is also deployed.

Government have no information about any recent large scale infiltration by Pakistani nationals into any part of the country along the Indo-Pakistan border including the border district of Kutch (Gujarat). However, constant vigilance all along the international border is being maintained.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, मालूम होता है कि देश की सुरक्षा और सैनिक दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कच्छ, गुजरात का और इस समय देश की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जितनी गम्भीरता से सारा विवरण आना चाहिये था उतनी गम्भीरता से इसको लिया नहीं गया है। यहां पर जो घुसपैठिए आते हैं, इस समय देश में कितने घुसपैठिए हैं, इसकी सरकार को कोई जानकारी नहीं है। बार-बार यह प्रश्न उठता है, सरकार की ओर से भी कहा जाता है और समाचार-पत्रों में भी आ रहा है कि देश के बहुत से भागों में पाकिस्तान के घुसपैठिए आ रहे हैं और वे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो इस देश की सुरक्षा और ला एण्ड आर्डर और देश के साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए घातक है। जब तक उनके सम्बन्ध में सरकार को पूरी जानकारी न हो तब तक न तो उसको रोका जा सकता है और न इस बारे में कोई उचित व्यवस्था की जा सकती है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बार्डर कच्छ क्षेत्र, जहाँ से घुसपैठिए आते हैं, वहां पर स्मगलिंग होती है। हमारे देश से बहुत सी आवश्यक वस्तुएं जैसे घी, चीनी इत्यादि इधर से उधर चली जाती हैं। इसके अलावा कुछ घुसपैठिए चोरी की नीयत से भी आते हैं, वे हमारे यहाँ से जानवरों को खोलकर ले जाते हैं, घरों का सामान ले जाते हैं।

**Not recorded.

सबसे अधिक खतरनाक तो वे घुसपैठिए हैं जोकि गुप्तचरी करने के लिए हमारे देश में प्रवेश करते हैं। जैसी कि सूचनाएं मिली हैं और समाचार पत्रों हैं छपा है, मिशाल के लिए 1. अगस्त, 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में गांधीनगर से बहुत बड़ी जानकारी दी है। इससे यह साबित होता है कि यह बहुत गम्भीर मामला है और इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इस समस्या पर सरकार को बहुत सक्रिय और कठोर कदम उठाना चाहिए। आपने बोर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स लगा दी है। मालूम होता है कि आप अभी जानकारी नहीं कर पाए हैं कि कितने इस देश में प्रवेश कर गए हैं। इसका मतलब है वह फोर्स यंगेष्ट नहीं हैं। उनको हमें हर तरह के इक्विमेंटस, वारलैस सैट और दूसरी सुविधाएं देनी चाहिए। क्या मंत्री जी बतलाएंगे कि सरकार इस संबंध में कोई विशेष प्रभावशाली कदम उठा रही है? सरकार कुछ ऐसे स्रोत बनाने का प्रयास करेगी, जिससे इन घुसपैठियों के बारे में जानकारी रखी जा सके? क्या सरकार कोई उच्चस्तरीय दल बनाने पर विचार कर रही है, जो इस बात का अध्ययन करे कि पिछले चार-पांच सालों में कितने घुसपैठिए आ गए हैं और उनसे हमारा कितना नुकसान हुआ है? भविष्य में उनको कैसे रोका जा सकता है?

जैसा कि समाचार पत्र में है और लोगों को सन्देह है कि कहीं असम जैसी स्थिति यहां पैदा न हो जाए। वहां घुसपैठिए आ गए और वहां विदेशी नागरिकों की समस्या पैदा हो गई। कहीं गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी लोग न आ जाएं और असम जैसी समस्या पैदा कर दें। जैसी कि खबर मिली है कि पैट्रो-डालर देश इनको मदद देकर इस क्षेत्र में लोगों को सम्पत्ति खरीदवा रहे हैं। उनके मकान हैं जायदाद है उनको धन दे रहे हैं और उनको परमानेन्टली सैटल कर रहे हैं। इस प्रकार देश की अर्थ व्यवस्था, सुरक्षा और सैनिक—तीनों मिलकर हमारे लिए बहुत गम्भीर सवाल पैदा कर देंगे। अगर यह बात सच्ची है, तो क्या इसके लिए मन्त्री जी उच्चस्तरीय जांच कराएंगे कि कितने लोगों ने उस क्षेत्र में सम्पत्ति खरीदी है और कितनों ने मकान बनवाये हैं और कितनों से अपने उद्योग-धन्धे उन क्षेत्रों में बसा लिये है? क्या वे इस देश के नागरिक हैं या पाकिस्तानी हैं?

इसके अलवा मैं मन्त्री जी का ध्यान खासतौर से इस बात पर दिलाऊंगा कि गुजरात सरकार ने स्वयं चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि सैकड़ो की संख्या में घुसपैठिए आ गए हैं। केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी दी है। क्या गुजरात सरकार ने आपकी सरकार को इसकी कोई सूचना दी है या चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि हमें मदद चाहिये? यदि हां, तो उनको आपने क्या सहायता दी है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या भविष्य में आप पाक नागरिकों को देश में आने पर रोकने के लिये कोई सक्षम कदम उठायेंगे? यदि वे उठायेंगे, तो आपको बहुत ही मजबूत कदम उठाना होगा, ताकि लोग देश में न आ सकें। कश्मीर में भी कभी-कभी ऐसी गड़बड़ियां होती हैं। यह भी कहा जाता है कि बहुत से साम्प्रदायिक दंगे हुए, उसमें उधर से पाकिस्तानी घुसपैठिए आए। गन्दा वातावरण पैदा किया और सांप्रदायिक विष फैलाया। कहा जाता है कि कुछ घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और आते हैं, वो आतंवाद फैलाते हैं। जो सहायता उनको पाकिस्तान की ओर से मिलनी चाहिये, वह सहायता किसी

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

तरह से एडजस्टमेंट करा देते हैं। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए क्या आपकी सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई विरोध प्रकट किया है ? पाकिस्तान ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और क्या पाकिस्तान की सरकार ने कोई आश्वासन दिया है ?

जालन्धर के पंजाब केसरी अखबार में 6 जुलाई के अंक में एक समाचार निकला है—

पाकिस्तान ने रावी का प्रवाह भारत की ओर मोड़ दिया। जिला गुरदासपुर के अनेक देहातों के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न। कमालपुर गांव खाली होने लगा। पाकिस्तान के दरियाई आक्रमण से सीमांत गांव को बचाने की योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब।"

इस तरह की कार्यवाहियां उस तरफ से होती रहती हैं। क्या हमने पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सम्पर्क कायम किया है तथा उन्होने क्या अश्वासन दिया है ?

पिछले पांच सालों में पाकिस्तान के कितने जासूस जासूसी करते पकड़े गये तथा हमारी सरकार को यहां पर और कितने जासूसों के होने का सन्देह है ?

मैं सरकार का ध्यान खास तौर से इस तरफ दिलाना चाहता हूं—इस मामले में विदेश मंत्रालय और, गृह मंत्रालय दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब घुसपैठिये देश के भीतर आ जाते हैं तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो घुसपैठिये अब तक पकड़े गये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? आपने जो संख्या बतलाई है वह बहुत थोड़ी है, आप कहते हैं 14 लोग पकड़े गये हैं, इसका मतलब है कि सरकार इस मामले में असफल रही है, जितने लोग पकड़े जाने चाहिये थे उतने पकड़े नहीं गए हैं, जितने कदम उनके विरुद्ध उठाये जाने चाहिये थे, उतने कदम सरकार उठा नहीं पाई है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह बात सही नहीं है कि सरकार इस बारे में न जानकारी रखती है और न इस बरे में चिन्तित है। जहां तक गुजरात सरकार का ताल्लुक है हमने गुजरात सरकार से जानकारी लेने के पश्चात ही यह बयान दिया है। उन्होंने इसके संबंध में ऐसी कोई चिन्ताजनक स्थिति जाहिर नहीं की है और उन्हीं के आधार पर यह बतलाया गया है कि कोई लार्ज-स्केल इन्फिलट्रेशन नहीं हुआ है।

जहां तक वार्डर का ताल्लुक है यह वार्डर केवल गुजरात और कच्छ तक सीमित नहीं है, दूसरे इलाकों में भी बहुत बड़ा वार्डर है। पाकिस्तान के साथ हमारा वार्डर राजस्थान में भी है, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भी है। राजस्थान से 1980 में 205 लोग आये, 1981 में 13 लोग आये। 1982 में 32 लोग आये। पंजाब में 1980 में 20 आये, 1981 में 130 आये, 1982 में 115 आये। जम्मू-काश्मीर में 1980 में 83, 1981 में 67, 1982 में 71 आये। इस प्रकार से जो अनआथोराइज्ड लोग आ जाते हैं उनको वापस भेजने के लिये कानूनी कार्यवाही की जाती है, कभी-कभी कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं तो थोड़ी देर हो जाती है लेकिन इस सम्बन्ध में बराबर कार्यवाही की जाती है। वैसे हर साल दो लाख लोग वैलिड-वीजा लेकर पाकिस्तान से आते हैं, उनमें से चार-पांच हजार ऐसे स्पिल-ओवर्स हैं जो रह गए हैं जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, बाकी लोग वापस भेजे गये हैं :

जहां तक स्मगलिंग का ताल्लुक है—स्मगलिंग जरूर इस इलाके में समुद्र के जरिए कुछ जगहों पर होती है और इस सम्बन्ध में गुजरात गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय ने फाइनेन्स मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने स्मगलिंग रोकने के लिए त्वरित कदम उठाये हैं, जिनके कारण स्मगलिंग की जो स्थिति है उसमें अवश्य कमी आयेगी।

जैसा मैंने कहा था—यह बार्डर बहुत बड़ा बार्डर है, राजस्थान का बार्डर करीब 1035 किलोमीटर का है, पंजाब का 547 किलोमीटर का है, जम्मू-काश्मीर का 781 किलोमीटर का है। इसमें 98 सिक्योरिटी बी. एस. एफ. फोर्स राजस्थान में है, 151 पंजाब बार्डर पर हैं। 368 जम्मू-कश्मीर के बार्डर पर हैं। इस प्रकार सिक्योरिटी का पूरा इन्तजाम किया गया है। बी. एस. एफ. की चैक-पोस्टें और ज्यादा बढ़ाने का प्रावधान किया जा रहा है।

12.05 hrs.

MR. DEPUTY-SpEAKER : The House stands adjourned to meet again at at 2.05 p.m.

The Lok Sabha then adjourned for lunch till five minntes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twelve minutes past Fourteen of the Clock.

MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*

CALLING ATTENTION TO MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE—*CONTD.*

REPORTED LARGE-SCALE INFITRATION OF PAKISTANI NATIONALS INTO KUTCH IN NORTH GUJARAT AND IN OTHER PARTS OF THE COUNTRY

श्री रशीद मसूद : (सहारनपुर) मोहतरम डिप्टी स्पीकर सम्हब, आज जो मसला जेरे बहस है, यह मसला सिर्फ कच्छ या गुजरात से मुताल्लिक नहीं है बल्कि मुकम्मल तौर पर हिन्दुस्तान से मुताल्लिक है। हिन्दुस्तान के बार्डर से मुख्तलिफ जगहों से जो लोग हिन्दुस्तान में आते हैं, चाहे किसी भी नीयत से आते हों, उन सब जगहों से इन लोगों की आमद को रोकना हम सब लोगों की मुश्तरका फर्ज है। इस फर्ज को हम कहां तक निभाते हैं, यही देखने के लिये, तय करने के लिये आज यह बात यहां उठाई गई है।

हमारे सामने आसाम का मसला है। यह मसला भयानक सूरत अख्तियार कर रहा है। आसाम में पहले भी इसी तरीके से लोग आते रहे। बार-बार इस पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर यह सवाल उठता रहा कि इनकी आमद को रोका जाये। कभी सरकार नें कहा कि कोई इस तरीके से लोग नहीं आ रहे हैं। कभी कहा कि इनको रोका जा रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ बयान दिए गए।

आज यह सिलसिला हमारे मगरबी सूबों में शुरू हो गया है। अखबारों में भी ये बातें आ रही हैं। पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क के लोग अगर गैर कानूनी ढंग से हमारे यहां आते हैं तो उनकी आमद को रोकना हमारा फर्ज है। कहीं मगरबी सूबों में भी यह भयंकर सूरत अख्तियार न कर ले जिसका सामना आज आसाम में करना पड़ रहा है। आसाम के मसले का भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। अभी जल्द ही किसी हल की सूरत नहीं दिखाई देती है। इस मामले को भी आसानी से और मामूली मामला समझकर इस पर बहस नहीं करनी चाहिये। आपने अपने जवाब में

[श्री रशीद मसूद]

लिखा है कि ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आ रहे हों। लेकिन अखबारों में ऐसी इत्तिला आई हैं, खबरें छपी हैं कि बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि अखबारों की खबरें गलत हैं या सही। लेकिन इस तरह की इत्तिला आप 1947 के बाद से आज तक असम के मामले में भी देते आ रहे हैं और मुख्तलिफ मौकों पर आपने कहा है कि बड़े पैमाने पर असम में लोग बाहर से नहीं आ रहे है। लोग आते रहे और सरकार यही जवाब देती रही कि हमारे पास कोई इस तरह की इत्तिला नहीं है कि बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। आज जो सूरत पैदा हो गई है वहां उसको सरकार हल नहीं कर पा रही है। नाअहली कहिये या अमल न करने की वजह से हो असम में इलैक्शन के दौरान और इलैक्शन के बाद जो खून खराबा हुआ, इन्सानी कत्लेआम का जो प्रोपेगंडा दुनिया में हुआ, हमारा इमेज खराब हुआ, बाहर के लोगों ने हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इस सबको लेकर हमारे मुल्क को जो बहैसियत मुलजिम के कठघड़े में खड़े हो जाना पड़ा वह हमारे सामने है। इस वास्ते अखबारों में जो रिपोर्ट आ रही हैं उनको आपको इतनी आसानी से टाल नहीं देना चाहिये। अगर आपने इस तरह से बाहर के लोगों को आने से नहीं रोका तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि आने वाले कल को फिर कहीं हमारे मुल्क को बहैसियत मुलजिम के दुनिया के सामने खड़ा न होना पड़ जाये और इस हिस्से में भी यह मांग न होने लग जाए कि हमारे कल्चर को, हमारे तमद्दुन को, हमारी जबान को खतरा पैदा हो गया है बाहर के लोगों की वजह से। इस वास्ते अकलमन्दी की बात यही होगी कि इस तरह से आसानी से जवाब न दिया जाए, बहुत सोच समझकर, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत सीरियसली इस मसले को टेक अप किया जाए।

आपने जवाब में कहा है कि 21 आउट-पोस्ट्स हैं जो आने वाली को चैक करती हैं। मैं जानता हूँ सेठी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और इत्तिफाक से जो दूसरे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं वे भी बहुत अच्छे आदमी हैं। यह मेरी परसनल राय है। कुछ लोग हैं जिनके बारे में अच्छी राय नही हैं। लेकिन इनके बारे में अच्छी राय है। लेकिन इसका मतलब यह हर्गिज नहीं है कि आप लोगों से जो कोताही हो रही है हम उसको प्वाइन्ट आउट न करें आपने लिखा है कि 21 आउटपोस्ट्स हैं जो इनफिल्ट्रेशन को चैक करती हैं। एक चैक पोस्टके हिस्से 24.385 किलोमीटर का फासला बैठता है क्योंकि 512 किलोमीटर लम्बा कच्छ का बोर्डर है। एक चैक पोस्ट पर कुल 25 नौजवान होते हैं। उसके हिसाब से देखेंतो एक आदमी के हिस्से में एक किलो-मीटर का इलाका आता है। जिसके ऊपर वह निगरानी रखता है, 24 घंटे, दिन और रात रखता है। यह जो नौजवानों की तादात है यह निहायत कम है। एक आदमी के लिये रात-दिन पहरा देना और एक किलोमीटर इलाके पर पहरा देना बहुत मुश्किल है। मेरी गुजारिश है कि चैक पोस्टस् की तादात को बढ़ाया जाना चाहिये। कम से कम दुगना किया जाना चाहिये। आध किलोमीमीटर का इलाका एक आदमी के पास देखभाल करने के लिए होना चाहिए हालांकि मैं समझता हूँ कि यह भी ज्यादा है लेकिन सब हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आध किलो-मीटर का इलाका ही उसके जिम्मे होना चाहिये। मुल्क की हिफाजत के रास्ते में

कोई भी मुश्किल आये तो हमें उसको हटाना होगा। मुल्क की हिफाजत करने के लिए चाहे जितनी मुश्किलात हमें उठानी पड़े, जितनी भी फाइनेंशियल दिक्कतें हमारे सामने आएं, उनको हमें दूर करना होगा और जब कभी मुल्क की हिफाजत का मसला आये तो कोई भी कंसिड्रेशन इसके अलावा हमारे सामने नहीं होनी चाहिये कि मुल्क की हिफाजत हर कीमत पर हो। मिलिट्री का मकसद यही है कि हमारे मुल्क की सीमाओं, हदूद की हिफाजत हो। हमारा मकसद भी यही है कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए, चाहे इकनामिक हो, सीमाओं की हिफाजत हो, ला एन्ड आर्डर की बात हो, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। यही हमारा फर्ज है।

आपने 21 चैक पोस्टें बनाई है और 25 आदमी लगाए हैं। एक आदमी के पास 1 किलोमीटर का इलाका आता है जिसकी उसे निगरानी करनी होती है, यह गैर-मुनासिब है। 25 में अगर 12, 12 घंटे की ड्यूटी 12 आदमी और 8 घन्टे की डयूटी लगायें तो 8, 9 आदमी बैठते हैं यानि 3 किलोमीटर का इलाका एक आदमी की निगरानी में आता है। मैं नहीं समझता कि कोई आदमी 3 किलोमीटर की निगरानी कर सकता है और इन-फिल्ट्रेटर को आने से रोक सकता है। मैं समझता हूँ कि आपने इस बारे में सोचना नहीं चाहा। रिपोर्ट आज भी आ रही हैं कि असम में अभी तक भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप तादाद बढ़ाइए और इतनी बढ़ाइए कि आदमी पूरे तरीके से हिफाजत कर सकें और कोई भी उधर से न आ सके।

मैं जानना चाहूँगा कि कितनी चैक-पोस्ट आप और बढ़ायेंगे और क्या इस पर भी गौर करेंगे कि मजीद आदमी बढ़ाए जाएं और क्या ऐसा भी करेंगे कि एक आदमी के जिम्मे आधा किलोमीटर की निगरानी ही आए और उसे 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न देनी पड़े ?

आपने यह भी बताया कि पिछले साल कुछ लोग और गिरफ्तार किये गए लेकिन इससे पहले सालों का आपने नहीं बतया कि मुख्तलिफ सालों में बार्डर पर मशकूक हालात में कितने लोग पकड़े गए जो बार्डर क्रास करके आ रहे थे ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह नम्बर बढ़ रहा हो ? इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बार्डर की हिफाजत के मामले में किसी किस्म की भी आपकी तरफ से कोताही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे बार्डर मुकम्मिल तौर पर सील हो जायें, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रशید مسعود (सहारनपुर):

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - آج جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ مسئلہ صرف کچھ باگرات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ہندوستان سے متعلق ہے، ہندوستان کے بارڈر جتنے مختلف جگہوں سے ان لوگوں کی آمد کو روکنا ہم سب لوگوں کا مشترکہ فرض ہے، اس فرض کو ہم کہاں تک نبھاتے ہیں دیکھنے کے لئے، طے کرنے کے لئے آج یہ بات یہاں اٹھائی گئی ہے۔

ہمارے سامنے آسام کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہار کی صورت اختیار کر رہا ہے، آسام میں بھی پہلے اس طریقے سے لوگ آتے رہے، کئی بار اس پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ سے باہر یہ سوال اٹھتا رہا کہ یہ ان کی آمد کو روکا جائے۔ کبھی سرکار نے کہا کہ کوئی اس طریقے سے لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ کبھی کہا کہ ان کو روکا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے مختلف موقعوں پر مختلف بیان دیئے گئے۔

آج یہ سلسلہ ہمارے مغربی صوبوں میں شروع ہو گیا۔ اخباروں میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں، پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، پاکستان سے یا کسی بھی ملک کے لوگ اگر غیر قانونی ڈھنگ سے ہمارے یہاں آتے ہیں تو ان کی آمد کو روکنا ہمارا فرض ہے، کہیں مغربی صوبوں میں بھی یہ بھیانک صورت اختیار نہ کرے جس کا سامنا آج آسام میں کرنا پڑ رہا ہے۔ آسام کے صوبے کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا ہے ابھی جلدی ہی کسی حل کی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے۔

اس معاملے کو ابھی آسانی سے اور معمولی معاملات سمجھ کر اس پر بحث نہیں کرنی چاہیئے،

آپ نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر باہر سے لوگ آرہے ہوں۔ لیکن اخباروں میں ایسی اطلاع آئی ہے، خبریں چھپی ہیں۔ کہ لوگ بڑے پیمانے پر آرہے ہیں۔

مجھے نہیں معلوم کہ اخباروں کی خبریں غلط ہیں یا صحیح لیکن اس طرح کی اطلاع آپ ۱۹۷۴ء کے بعد سے آج تک آسام کے معاملے میں بھی دیتے آرہے ہیں اور مختلف موقعوں پر آپ نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر آسام میں لوگ باہر سے نہیں آرہے ہیں۔ لوگ آتے رہے اور سرکار یہی جواب دیتی رہی کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر آرہے ہیں۔ آج جو صورت حال پیدا ہو گئی ہے۔ وہاں سرکار اس کو حل نہیں کر پا رہی ہے۔ نااہلی کے لئے یا عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی آسام میں الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد جو خون خرابہ ہوا، انسانی قتل عام کا جو پروپیگنڈہ دنیا میں ہوا، ہمارا امیج خراب ہوا۔ باہر کے لوگوں نے ہمارے ملک میں آکر ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سب کو لے کر ہمارے ملک کو بحیثیت ملزم کے کٹہرے میں کھڑے ہو جانا پڑا۔ وہ ہمارے سامنے ہے، اس واسطے اخباروں میں جو رپورٹ آرہی ہے، اس کو آپ اتنی آسانی سے ٹال نہیں دینا چاہیئے۔ اگر آپ نے اس طرح سے باہر کے لوگوں کو آنے سے نہیں روکا۔ میں نے نہیں کہہ سکتا کہ آنے والے کل کو پھر کہیں ہمارے ملک کو بحیثیت ملزم کے دنیا کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے اور اس حصہ میں بھی یہ مانگ نہ ہونے لگ جائے تو ہمارے کلچر کو، ہماری تمدن کو ہماری زبان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، باہر کے لوگوں کی وجہ سے، اس واسطے عقلمندی کی بات یہی ہو گی کہ اس طرح سے آسانی سے جواب نہ دیا جائے، بہت سوچ سمجھ کر، بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت سیریس اس مسئلے کو کو ٹیک اپ کیا جائے۔

آپ نے جواب میں کہا کہ ۲۱ آؤٹ پوسٹیں ہیں جو آنے والوں کو چیک کرتی ہیں، میں جانتا ہوں سیٹھی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور اتفاق سے جو دوسرے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں، یہ میری پرسنل رائے ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں اچھی رائے ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جو کوتاہی ہو رہی ہے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ آپ نے لکھا ہے کہ ۲۱ آؤٹ پوسٹیں ہیں جو انفلٹریشن کو چیک کرتی ہیں، ایک چیک پوسٹ کے حصے میں ۳۸۵ سے ۴۴۳ کلومیٹر کا فاصلہ بیٹھتا ہے۔ یعنی کہ ۵۱۲ کلومیٹر لمبا چھ کا بارڈر ہے، ایک چیک پوسٹ پر کل ۲۵ نوجوان ہوتے ہیں، اس کے حساب سے دیکھیں تو ایک آدمی کے حصے میں ایک کلومیٹر کا علاقہ آتا ہے۔ جس کے اوپر وہ نگرانی رکھتا ہے، ۲۴ گھنٹے دن رات رکھتا ہے۔ یہ

جو نوجوانوں کی تعداد ہے یہ نہایت کم ہے، ایک آدمی کے لئے رات دن پہرہ دینا اور ایک کلومیٹر علاقے پر پہرہ دینا بہت مشکل ہے، میری سفارش ہے کہ چیک پوسٹ کی تعداد کو بڑھایا جائے، کم سے کم دوگنا کیا جانا چاہیئے۔ آدھا کلومیٹر کا علاقہ ایک آدمی کے پاس دیکھ بھال کے لئے ہونا چاہیئے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادہ ہے لیکن سب حالات کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آدھا کلومیٹر کا علاقہ ہی اس کے ذمہ ہونا چاہیئے۔ ملک کی حفاظت کرنے کے لئے چاہے کتنی مشکلات ہمیں اٹھانی پڑیں۔ کتنی بھی فائنینشل دقتیں ہمارے سامنے آئیں ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا۔ اور جب کبھی ملک کی حفاظت کا مسئلہ اٹھے تو کوئی بھی کنسیڈریشن اس کے علاوہ ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیئے۔ کہ ملک کی حفاظت ہر قیمت پر ہو۔ ملٹری کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک کی سیماؤں کے حدود کی حفاظت ہو، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ملک کی حفاظت کے لئے چاہے اکٹھا ملک ہوں، سیماؤں کی حفاظت ہو لا اینڈ آرڈر کی بات ہو، ہم سب ملک مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں جس سے ہمارا ملک ترقی کرے یہ ہی ہمارا فرض ہے۔

آپ نے ۲۱ چیک پوسٹیں بتائیں اور ۲۵ آدمی لگائے ہیں، ایک آدمی کے پاس ایک کلومیٹر کا علاقہ آتا ہے جس کی اسے نگرانی کرنی ہوتی ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ ۲۵ میں اگر بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی لگائیں، بارہ آدمی اور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی لگائیں تو آٹھ نو آدمی بیٹھتے ہیں یعنی تین کلومیٹر کا علاقہ ایک آدمی کی نگرانی میں آتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی تین کلومیٹر کی نگرانی کر سکتا ہے اور انفلٹریشن آنے سے روک سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں سوچا نہیں چاہا۔ رپورٹ آج بھی آرہی ہے کہ آسام میں ابھی تک لوگ آرہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ آپ تعداد بڑھائیے اور اتنی بڑھائیے کہ آدمی پورے طریقے سے حفاظت کر سکے۔ اور کوئی ادھر سے نہ آسکے

میں جاننا چاہوں گا کہ کتنی چیک پوسٹ آپ اور بڑھائیں گے اور کیا اس پر بھی غور کریں گے کہ مزید آدمی بڑھائے جائیں اور کیا ایسا بھی کریں گے کہ ایک آدمی کے ذمہ آدھا کلومیٹر کی نگرانی آئے اور اسے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہ دینی پڑے

آپ نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے سال کچھ لوگ اور گرفتار کئے گئے۔ لیکن اس سے پہلے سالوں کو آپ نے نہیں بتایا کہ مختلف سالوں میں بارڈر پر مشکوک حالت میں کتنے لوگ پکڑے گئے جو بارڈر کراس کر کے آرہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نمبر بڑھ رہا ہو۔ اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیئے۔ بارڈر کی حفاظت کے معاملے میں کسی قسم کی بھی آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیئے۔ بلکہ ہمارے بارڈر مکمل طور پر سیل ہو جائیں اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں۔

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य का कसूर मानता हूँ कि उन्होंने देश के ख्याल से इस मसले को उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान के बार्डर का मुकाबला असम के वार्डर से किया है। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि असम में स्थिति और है। असम में 1971 तक जो लोग बंगला देश से आये हैं वह हमारे एक दूसरे देशों के बीच हुए विभिन्न करारों के तहत आये हैं। इसके अलावा यहां की स्थिति और वहां की स्थिति में फर्क है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वहां की नागरिकता का मामला अब तक तय किया जा रहा है। इससे पहले 1 लाख लोग वापिस भेजे जा चुके हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बार्डर पर चैकपोस्टों का फासला 3, 4. किलोमीटर कर दिया गया है। जैसा यहां पर है, उतना फासला वहां नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है कि इस तरफ से भी लोग आते हैं। जैसा पूर्व-उत्तर में बताया गया है, यह संख्या काफी कम है और इसको रोकने के लिए न केवल बार्डर सिक्योरिटी कोर्स इस्तेमाल की जाती है, बल्कि लोकल राज्य की पुलिस भी इस्तेमाल की जाती है। हम इसको बड़े पैमाने पर होने देना गवारा नहीं करेंगे और बराबर कोशिश करेंगे कि जो थोड़ी बहुत तादाद में इनफिल्ट्रेटर्ज आ रहे हैं, वे न आएं। लेकिन हमारा बार्डर ऐसा है और इतना बड़ा है कि लोग अपने रिश्तेदारों के पास इधर-उधर आते रहते हैं। जब कोई बिना किसी बाजिब दस्तावेज के चला आता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। मैं माननीय सदस्य और सदन को अश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम बार्डर चैकपोस्ट बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कितनी बढ़ा पाएंगे अभी मैं नहीं कह सकता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मान्यवर आज हम एक बहुत गम्भीर विषय पर विचार कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक हमारे देश की सुरक्षा और आजादी से है। स्वाधीनता के साथ ही देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। दोनों देशों के समन्वय बिगड़ गए, काफी तनाव उत्पन्न हुआ और हमारे देश को पाकिस्तान के साथ तीन युद्ध भी लड़ने पड़े —1948 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध। 1971 का युद्ध तो इतना बड़ा हुआ कि उसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान दो भागों में बंट गया और एक नए देश-बंलादेश-का जन्म हुआ।

इस युद्ध के बाद पाकिस्तान की सीमा छोटी हो गई, उसका क्षेत्रफल सकुचित हो गया। लेकिन सीमा के छोटा होने पर भी पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में काफी इजाफा हुआ है' जो बड़ी चिन्ता का विषय है। पाकिस्तान को 6,000 किलोमीटर भूमि-सीमा की रक्षा करनी पड़ती है, जबकि हमारे देश को 15,200 किलोमीटर भूमि-सीमा की रक्षा करनी पड़ती है। पाकिस्तान की तटीय सीमा 900 किलोमीटर है, जबकि हमारी तटीय सीमा 6,000 किलोमीटर है।

यदि हत गहराई से देखें, तो इतनी लम्बी सीमा की रक्षा के लिए वर्तमान सैनिक, सीमा-रक्षक और वार्डर चौकियां बहुत कम हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर है। हमारी जो सीमाएं हैं: गुजरात-पाकिस्तान सीमा, पजाब-पाकिस्तान सीमा जम्मू-काश्मीर सीमा और राजस्थान सीमा, उनपर विशेष गड़बड़ियाँ हैं। अभी-अभी उत्तरी कमान और गृह विभाग के सूत्रों द्वारा पता चला है कि 6 जुलाई 1983 को एक पाकिस्तानी बिमान ने जम्मू क्षेत्र में असनूर क्षेत्र पर उड़ान भरी और

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

वह आधे घंटे तक एक भारतीय सीमा में काफी दूर तक उड़ान भरता रहा। 9 जुलाई को सेहरा गांव में, जो भारतीय सीमा से डेढ़ किलोमीटर दूर है, पाकिस्तान ने एक शक्तिशाली रैडार स्थापित किया है। गुजरात पाकिस्तान सीमा पर बहुत गड़-बड़ियां हैं।

सीमाओं पर ही नहीं, देश के विभिन्न शहरों—कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद और मेरठ आदि—में समय-समय पर पाकिस्तानी घुसठिपैए पकड़े जाते हैं।

अब मैं पंजाब से निकलने वाले अखबार पंजाब केसरी की एक कटिंग में से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह बड़ा महत्वपूर्ण अखबार है। मैं मन्त्री महोदय से कहूँगा कि वह इन शब्दों पर जरूर ध्यान दें।

"भारतीय चौकी पर पाक सेना द्वारा कब्जा। चौकी खाली कराने की सीमा वार्ताओं का नतीजा कुछ न निकला। चीनी लड़ाकू विमान भारतीय क्षेत्र में घुसा कश्मीर सीमा पर पाक ने एक डिवीजन सेना बटा दी।"

यह तो मुख्य खबरें हैं और इसके नीचे जो लिखा है वह बहुत ही गम्भीर है;

"पाकिस्तानी सेना ने बारामूला सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भारतीय सैनिक चौकी पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र में एक ओर जहां पाकिस्तान ने एक डिवीजन सेना और फौंक दी वहीं दूसरी ओर एक चीनी लड़ाकू विमान ने आधे घंटे तक भारतीय वायु क्षेत्र में घुसकर गुप्तचरी की। रक्षा मंत्रालय के निदेश पर भारतीय सैनिक अधिकारियों ने पाक सैनिक अधिकारियों के साथ सीमा चौकी खाली कराने के लिए कई फ्लैग मीटिंग की परन्तु पाक सेना ने सीमा चौकी खाली करने से इन्कार कर दिया है।

आगे लिखते हैं:

"एक अज्ञात विमान ने 31 जुलाई को भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया। उक्त विमान लद्दाख के प्रतापपुर सेक्टर के ऊपर लगभग 20 मिनट तक उड़ान भरता रहा।"

फिर आगे एक लम्बी खबर के बाद लिखते हैं:

"इसी बीच भारतीय प्रतिरक्षा अधिकारी पाकिस्तानी सैनिकों से कश्मीर घाटी के बारामूला सेक्टर में उनके द्वारा हाल ही में अधिगृहीत की गई सामरिक चौकी खाली करवाने के प्रयास कर रहे है। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा उस चौकी पर कब्जा किए जाने का पता तब चला जब बर्फ पिघलने व दर्रे साफ हो जाने के कारण बाद भारतीय प्रतिरक्षा इकाई पोजीशन लेने के लिए वहां वापिस आई।"

आगे लिखते हैं:

"यहां प्राप्त विश्वस्त सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग पिछले तीन वर्षों में और एक डिवीजन सेना तैनात कर दी है। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में अत्याधुनिक राडार भी लगा दिए हैं। एक उच्च शक्ति वाला राडार हाल ही में कोटली में स्थापित किया गया।"

इसको देखने के बाद इस विषय की गम्भीरता का अहसास हो रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज यह सबसे ज्वलन्त

समस्या हमारे सामने है आज मैं अखबार देख रहा था तो उसमें भी यह है कि गुजरात सीमा की ओर उनके कुल सैनिक चले आए। अभी मेरे से पहले जब श्री रशीद मसूद ने प्रश्न किया था तो उन्होंने असम और बंगलादेश की बात कही थी और मन्त्री जी ने बताया था कि उन सीमाओं की हालत भिन्न है। लेकिन मैं यह बता दूं कि वहां पर जो भी हालात हो लेकिन बंगलादेश से असम में जो लोग आ रहे थे उनको रोकने के लिए उस सीमा पर तार लाइन या दीवार बनाने का प्रपोजल रखा गया था जिसका बंगलादेश के राष्ट्रपति ने विरोध किया। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो चारों-पांचो सीमायें हैं, राजस्थान की सीमा पंजाब की सीमा, गुजरात की सीमा, जम्मू-कश्मीर की सीमा-इन सीमाओं पर भी क्या कोई बार्डर लाइन तार वगैरह लगाने का विचार है या नहीं ? यदि है और बंगलादेश की तरह से पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी उसका विरोध किया तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे ? इसमें तो कोई सन्देह नहीं है, जैसा कि और भी वक्ताओं ने भी कहा है और मन्त्री जी ने स्वीकार भी किया है कि बराबर लोग चले आ रहे हैं- पूर्व में भी आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जो घुसपैठिए हमारे यहां आ रहे हैं उसी तरह से क्या हमारे देश से भी कुछ लोग वहां जाते हैं और क्या कभी इस बारे में पाकिस्तान सरकार ने हमारी सरकार से कोई शिकायत की है कि हिन्दुतान के लोग भी पाकिस्तान की ओर आते हैं, अमृतसर की ओर से या कच्छ की ओर से-यदि ऐसी शिकायत आई है तो कितने केसेज सामने आए हैं और कितने हमारे लोग वहां जाकर पकड़े गए हैं ?

कुछ दिन पहले हमारे देश के नेताओं ने भी कहा था, मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं करता क्योंकि यह देश का सवाल है, मैं संजीदगी के साथ पूछता हूं कुछ लोगों ने अभी कहा था और जैसा राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था। जम्मू-काश्मीर के इलैक्शन में कि हमको पाकिस्तान से कुछ खतरा है। पड़ोसी मुल्कों से कुछ परेशानियां हैं। इस बात को उन्होंने गोल मोल तरीके से कहा था। राजीव जी ने सीधे-सादे ढग से कहा था कि हमारे यहां जो यह अकाली का मामला चल रहा है, इसमें भी कुछ उधर के लोगों का हाथ प्रतीत होता है। एक बात मैं अधिकारी वर्ग से भी जानना चाहूंगा, हमारे देश की कुछ ज्वलन्त समस्यायें हैं, जिससे यह सदन और पूरा देश चिन्तित है और जिस में गृह मंत्री जी का आधे से ज्यादा समय खर्च हो जाता है, क्या इन समस्याओं में इन घुस-पैठियों का हाथ है या नहीं है ? इसी संदर्भ में मैं एक बात यह भी जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान से या बंगला देश से या चारों सीमाओं से जो शरणार्थी देश के अन्दर आते हैं, क्या इसकी शिकायत संयुक्त राष्ट्र संघ के रिफयूजी रिलीफ आर्गेनिजेशन से की है ? क्या उनके सामने यह मामला ले जाया गया है ? क्या हम इनको शरणार्थी मानने के लिए तैयार हैं और क्या इनके बारे में कोई नई बातें प्रकाश में आई हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट खत्म हो गए हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हिन्दी में बोले हैं। मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं दो-चार बातें और कहना चाहूंगा। किशनगंज, बिहार, के डी. एम. ने वहां की मतदाता सूची का निरीक्षण कराया तो

[श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री]

उसमें तीन हजार ऐसे लोग पाए गए, जो घुसपैठिए हैं और बाहर के लोग यहां आकर नागरिक बन गए हैं। यहां पर भी असम जैसी समस्या पैदा होने की संभावना है। उसमें कई उच्च अधिकारियों को सस्पैंड किया गया है इतना ही नहीं पूर्णिया में बार्डर से भट्टी मुसलमान लोग आते हैं। वहां पर अभी एक आदिवासी नेता, जपना सौरण, का मर्डर हुआ है। वहां के उच्च अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है, उसमें इन्हीं घुसपैठियों का ही हाथ लगता है। यहां पर भी चर्चा हुई थी। मैं आपके माध्म से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, अहम मसला है, क्या आपका ध्यान इस ओर है या नहीं है ? इसको रोकने के आप क्या उपाय कर रहे हैं ? मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि जिन घुसपैठियों को आप पकड़ लेते हैं, उनको वापिस करने के लिए, उस देश में भेजने के लिए, क्या आपकी कोई वहां की सरकार से बातचीत होती हैं ? कई बार आप की विदेश मंत्री से भी बातचीत होती है और जो राजनीतिक लोग आते हैं, क्या उन से भी इस बारे में बातचीत होती है? मैं यह जानना चाहता हूं पिछले तीन-चार वर्षों में कितने घुसपैठियों को अपने पकड़ा और कितनों को वापिस उनके देश में भेज दिया है ?

आखिरी बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के समाचार पत्र निरन्तर गलत बातें छापते हैं, जबकि वहां मिलिट्री रूल है, वहां पर खबरों की पाबन्दी हैं, वहां एक-एक समाचार सैंसर होता है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के एक समाचार पत्र "नवा-ए-वक्त" में हमारे देश की प्रधान मंत्री का एक कार्टून निकाला गया है। जिसमें दिखाया गया हैं कि प्रधान मंत्री अरब देश के सौदागरों के साथ खड़ी हैं और मुसमुरा रही हैं और प्रधान मंत्री का बहुत गन्दा चित्र था कि कुछ कहने की बात नहीं है। हम उस शब्द को जुबान पर लाना नहीं चाहते। उनकी कमर से तलवार लटक रही है और तलवार से खून टपक रहा है, सामने पाकिस्तानी लोग खड़े हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक अन्य कार्टून की तरफ भी दिलाना चाहता हूं- इस में एक ओर पाकिस्तान के मुसलमान हैं और दूसरी ओर हिन्दुस्तान के हिन्दुस्तानी लोग हैं, बीच में महात्मा गांधी खड़े हैं। महात्मा गांधी के हाथ में एक बन्दूक है जिसे वह मुसलमानों की ओर, पाकिस्तानी जनता की ओर ताने हुए हैं। वहीं पर पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल खड़े हो कर मुस्कुरा रहे है। नीचे लिखा हुआ है-हम अहिंसावादी हैं। यह कितना बड़ा अपमान है, कितनी सीरियस बात है। मैं जानना चाहता हूं-क्या हमारी सरकार ने इस के विरोध में पाकिस्तान को कोई विरोध पत्र भेजा ? यहां के अखबारों में दोनों कार्टूनों की काफी चर्चा हुई है, हमारे पास उनकी कटिंग्ज मौजूद हैं। "यह हिन्दुस्तान" दैनिक की खबर है। यदि विरोध पत्र भेजा गया है तो वहां की सरकार ने क्या जवाब दिया है ? यदि किसी कारणवश इस तरफ आप का ध्यान न गया हो तो आज जो चर्चा की जा रही है कि पाकिस्तान में इस तरह के कार्टून छप रहे हैं, ऐसी खबरें छापी जा रही हैं-क्या हमारा मंत्रालय पाकिस्तान के साथ इन बातों के बारे में विरोध प्रकट करेगा ?

महात्मा गांधी फिल्म यहां पर बनी, हमारी सरकार ने उस पर 6 करोड़ रुपया

खर्च किया। पाकिस्तान सरकार ने यह कहा कि महात्मा गांधी फिल्म में डाक्टर अम्बेदकर को नहीं दिखलाया गया है। हम मुहम्मद जिन्ना के सम्बन्ध में और पाकिस्तानी अक्सरियत के सम्बन्ध में एक फिल्म बना रहे हैं उस में दिखलायेंगे। यह कितना गम्भीर मामला है। यह बात हमारे यहां उठती कि "गांधी" फिल्म में डाक्टर अम्बेदकर को नहीं दिखलाया गया है तो मैं उस बात को समझ सकता था। लेकिन वहां दिखला कर इस तरह से लोगों को भड़काना यह बहुत गम्भीर मसला है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत काफी था, लेकिन चूंकि आप ने पहली बार आदेश हिन्दी में दिया है, इस लिये आप की आज्ञा का पालन कर के बैठ जाता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य ने बहुत सारे मामलों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का जहां तक ताल्लुक है, कोई शरणार्थी पाकिस्तान से भारतवर्ष में इन दिनों में नहीं आया है। उन्होंने जिन का जिक्र किया है वे घुसपैठिये हैं, अनधिकृत लोग हैं, जो बिना किसी अधिकृत डाक्यूमेन्ट के हिन्दुस्तान की सीमा में चले जाते हैं। उन को पकड़ा जाने के बाद उन की सीमा पर वापस छोड़ दिया जाता है। इस में पाकिस्तान से कहने का कोई सवाल नहीं है और जैसा मैंने बतलाया था, इन की संख्या इतनी कम है—जैसा मैंने 1980, 1981, 1982 में पंजाब, राजस्थान और जम्मू-काश्मीर के सम्बन्ध में सुबह बतालाया था-इस पर कार्यवाही करना हमारी बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और वहां की जो लोकल पुलिस है दोनों के लिये असम्भव है। इसके अलावा हम इन्टैलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस के इंटैलिजेंस से इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखते रहते हैं तथा इस प्रकार की कार्यवाही होने नहीं देते जिस से हिन्दुस्तान को खतरा हो।

जहां तक बारामूला की एक चौकी पर कब्जे का प्रश्न है-यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराऊंगा और जो कार्टून्ज निकले हैं उन के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय ही पाकिस्तान की सरकार के सामने विरोध पत्र दे सकता है। माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, वह विदेश मंत्रालय तक अवश्य पहुंचा दूंगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : इन्होंने बिहार के बारे में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : बिहार की सीमा सीधे किसी अन्य देश से नहीं लगती है लेकिन यह बात सही है कि बिहार में कुछ लोग बंगाल के जरिये प्रवेश कर रहे है, उन को रोकने का कड़ा प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं ने दीवार के बारे में पूछा था ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दीवार का या वायर फेंसिग का जहां तक सवाल है, असम और बंगलादेश का जितना भी वोर्डर है, उस पर बनाने का फैसला हुआ है लेकिन पश्चिमी सीमा पर क्योंकि आने वालों की तादाद इतनी कम है कि हमारी जो सेक्यूरिटी फोर्स है, उन चैक-पोस्टों के जरिये से इस चीज को रोका जा सकता है, इसलिए वहां पर फेंसिग न करने की कोई आवश्यता नहीं है

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्क्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य आया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मामला इतना गंभीर नहीं है जैसा कि कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया है और माननीय मंत्री जी ने हम सब को आस्वस्त कराया है कि बोर्डर पर पूरे तौर पर चौकसी रखी जाएगी और अनधिकृत लोग घुसपैठ कर के इस तरफ नहीं आएगें। मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और उस में जो स्थिति बताई गई है, उस पर शुबाह करने की गुंजाइश नजर नहीं आती है लेकिन मैं एक बात की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना आवश्यक समझता हूं और जिस का जिक्र हमारे पूर्व-वक्ता शास्त्री जी ने भी किया है। हमारे बोर्डर की स्थिति बहुत कुछ पाकिस्तान की अन्दरुनी स्थिति पर निर्भर करती है। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्रोपेगेन्डा शुरू हो गया है और भारत विरोधी रुख पाकिस्तान की सरकार द्वारा अपनाए जाने की बात भी हो सकती है। इस का मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान में अब जो जनतांत्रिक शक्तियां हैं, पार्टियां हैं, उन्होंने वहां के फौजी शासकों के खिलाफ जनतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जाहिर है कि वे सेंसर्ड रिपोर्टें होंगी और बहुत साफ-साफ रिपोर्टें पाकिस्तान के अन्दर से नहीं आ रही होंगी लेकिन जो रिपोर्टें मिल रही हैं उन से यह अन्दाजा लगाता है कि वहां जो सत्याग्रह चल रहा है जनतंत्र की बहाली के लिए, वह काफी जोरों पर है और वहां पर सिंध प्रान्त में और लगभग हर जगह वह फैल गया है और सीमावर्ती प्रान्त पंजाब में भी वह शुरू होने वाला है। पिछला तजुर्बा हम को यह बतलाता है कि जब-जब पाकिस्तान के मिलिट्री शासक और ऐसी शक्तियां दो-चार होती हैं, जब-जब वहां जनतंत्र की बहाली का संघर्ष होता है, तब-तब ये फौजी शासक जनता का ध्यान भारत से खतरे की तरफ ले जाते हैं और कोई भी ऐसी गतिविधि जरूर करते हैं, जिस से हमारे बोर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। 1971 की बात हम को याद है। इसी कच्छ में तनाव पैदा हुआ था। जम्मू व कश्मीर में किस तरह से घुसपैठ हुई और आ कर उन्होंने क्या क्या हरकतें की थीं, ये सारी चीजें हम को मालूम हैं और हम से ज्यादा गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय को इस की सूच न होगी। तो मैं इस खतरे की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अब वह स्थिति पैदा हो गई है जैसा कि जनरल अयूब के खिलाफ हुई थी याहिया के खिलाफ हुई थी और वह स्थिति अब जनरल जिया के खिलाफ पैदा हो गई है और हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे बोर्डर पर कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो जाए। तो इस से हम सब लोगों को और खासकर हमारी सरकास को चौकस रहना चाहिए। जिस ढंग से बोर्डर पर चौकसी का काम हो रहा है, इस तरह की स्थिति को देखते हुए हमारी चौकसी और तेज होनी चाहिए और संगठित होनी चाहिए और ऐसी स्थिति पैदा न हो कि फिर से घुसपैठिये किसी तरह हमारे यहां आ सकें। अभी आज ही के समाचार पत्रों में निकला है कि 15 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे फहराय गये ये क्यों फहराये गये और किस ने फहराये? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

क्योंकि 1971 में भी पाकिस्तान से घुसपैठिये कश्मीर में आये थे। कहीं ऐसा

तो नहीं है कि फिर घुसपैठिये वहां से आने शुरू हो गये हों और उन्होंने कश्मीर में आग भड़काने के लिए और कश्मीर में कुछ करने के लिए यह हरकत की हो कि वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया हो। जब माननीय मंत्री जवाब दें तो जो 15 अगस्त को कश्मीर में जो घटना घटी है उसके बारे में बताने की कृपा करें।

पाकिस्तान में पैदा हो रही स्थिति पर हमारे बार्डर की स्थिति डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में जनतंत्र की बहाली का आन्दोलन तेज हो गया है और जब वहां के मिलिट्री शासक यह प्रयास करेंगे कि वहां की जनता का ध्यान जनतंत्र की बहाली की तरफ से मोड़ कर भारत के झगड़े की तरफ लगा दें।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यक्ष से एक बात और कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा बार्डर लगा हुआ है उससे हो कर अगर बदनीयति से घुसपैठिये आ रहे हैं तो उसे रोकना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक सच्चाई यह भी है कि बार्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग आपस में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और बहुत से तो एक ही खान्दान के हैं। एक ही खान्दान के कुछ लोग बार्डर के इधर भी रहते हैं क्योंकि यह तो हमारे देश की ऐसी स्थिति रही कि देश का बंटवारा हो गया लेकिन बंटवारे से खान्दान और धर्म तो नहीं बदल जाते, दिल तो नहीं बदला करते। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा प्रावधान हमारे दोनों देशों के बीच में है जिससे कि बोर्डर के इधर-उधर रहने वाले लोग एक-दूसरे से मिलने के लिए आमूली आधार पर आ जा सकते हों? उनके पास कोई ऐसा मुस्तकिल डाकुमेंट या दस्तावेज होना चाहिए जिसके द्वारा वे यहां आ जा सकें। अगर उनको जबर्दस्ती रोका जाएगा तो इससे भी इन्फिलट्रेशन होता रहेगा। आपकी सीमा पर जो चौकसी करने वाले लोग हैं, आपकी फोर्स है, वह भी इस प्रकार का इन्फिलट्रेशन करती रहती है और लोग उससे नाजायज फायदा उठाकर काम करते हैं। क्या इस तरह का कोई समझौता पाकिस्तान के साथ नहीं है या है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर नहीं है तो मैं समझता हूं कि मानवीय आधार पर इस प्रकार का समझौता होना चाहिए कि बार्डर के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं वे आसानी से अपने रिश्तेदारों, नातेदारों से मिलने के लिये आ जा सकें।

मुझे खुशी है कि हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रही है जिससे कि बार्डर से चीजें इधर-उधर आ जा सकें। मुझे यह भी खुशी है कि पाकिस्तान ने भी दिलचस्पी दिखाई है और हमारा एक ट्रेड डेलीगेशन पाकिस्तान गया था। हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्कान में पसन्द की जाती है और पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहां पसन्द की जाती हैं। अगर उनका आदान-प्रदाद हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो लोग गलत तरीके अपनायेंगे और स्मगलिंग करेंगे।

मुझे पता चला है कि पाकिस्तान में पान नहीं मिल रहा है। बहुत से पाकिस्तानी पान न मिलने की वजह से बड़ी मुश्किल में हैं। बंगलादेश में पान होता है और पहले वहां से पान पाकिस्तान को जाता था। अब वह वहां से नहीं जा रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : 'Pan' is being smuggled from India to Pakistan. Yau can be liberal. You can allow. Whenever anybody comes to South India, we offer 'Pan' as a mark of respect. If

[Mr. Deputy Speaker]

'Pan' goes to Pakistan from India, we should not object.

SARI GAULAM NABI AZAD (Washim) : Housing Department may not appreciate it.

श्री जैनुल बशर : हमारे यहां से वहां पान की स्मगलिंग हो सकती है। हमारे यहां और भी बहुत-सी दूसरी चीजें जो पाकितान में पसन्द की जाती हैं। हमारे यहां की बनारसी साड़ियां पाकिस्तान की महिलाएं बहुत पसंद करती हैं और वे उन्हें पहनना चाहती है। इस तरह से ऐसी चीजों के व्यापार की तरफ हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि ये चीजें गलत तरीके से इधर-उधर न जाएं बल्कि सही तरीके से इधर-उधर आएं जाएं। सही तरीके से उनका आना जाना शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान की ताजा स्थिति को देखते हुए और पिछले तजुरबों को देखते हुए सरहदों पर कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं। चौकियों के बारे में बताया है कि चौकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आने वाले खतरे को देखते हुए आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान के चाहने के बावजूद ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जिन चौकियों का जिक्र किया गया है वे घुसपैठियों को रोकने के लिए हैं। पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति का ताल्लुक है, उससे उत्पन्न किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए केवल चौकियां पर्याप्त नहीं हैं बल्कि हमारा सैनिक संगठन भी उनका जवाब देने के लिए तैयार है। इस बारे में अधिकृत रूप से तो रक्षा मंत्री जी ही बता सकते हैं, लेकिन आप जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि हम कोई सोए हुए नहीं हैं कि पाकिस्तान कोई शरारतपूर्ण कार्यवाही हिन्दुस्तान के खिलाफ करेगा और हम गफलत में पकड़े जाएंगे और हमारा कोई नुकसान हो जाएगा।

जहां तक कश्मीर में 15 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी झण्डा फहराया जाने का सवाल है, यह घुसपैठियों का काम नहीं है। कश्मीर में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारतवर्ष के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। उनमें से ही कुछ लोगों द्वारा यह कार्यवाही की गई है। इसके लिए हमने राज्य सरकार से जानकारी ली है और उनसे कहा है कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

बार्डर पर जो लोग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वे एक दूसरे के रिस्तेदार है। इसलिए प्रतिवर्ष लगभग दो-ढाई लाख आदमी आते जाते हैं। उनको आसानी से वीसा प्रदान किया जाता है। लेकिन इस तरह की छूट बार्डर पर रहने वालों के लिए दी जाए कि वे इधर से उधर या उधर से इधर आ जा सकें, यह हमारी सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होगा और संभवतः पाकिस्तान सरकार भी इसको मंजूर नहीं करेगी।

14.58 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we go to next item-Matters under Rule 377.

(i) Decline In Procurement Of Iron ore From Non-Captive Mines Of Orissa.

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak) : Sir, the steel plants used to procure 1.72